**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**आर्थिक कार्य विभाग**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या 207**

**(जिसका उत्तर मंगलवार, 01 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है।)**

**आर्थिक असमानता को दूर किया जाना**

**207. श्रीमती छाया वर्मा:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में आर्थिक असमानता में निरंतर वृद्घि हो रही है जिसके फलस्वरूप गरीब व्यक्ति और अधिक गरीब तथा अमीर व्यक्ति और अधिक अमीर होते जा रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा बढ़ती आर्थिक असमानता को दूर करने की दिशा में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और ऐसे क्या कारण हैं जिनके फलस्वरूप इस संबंध में उठाए गए कदमों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)**

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**श्रीमती छाया वर्मा द्वारा पूछे गए, 01 जनवरी, 2019 को उत्तरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 207के उत्तर में संदर्भित विवरण।**

(क): महोदय, एनएसएसओ के 2004-05 (61वाँ दौर) तथा 2011-12 (68 वाँ दौर) के पंचवार्षिक घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में मिश्रित संदर्भ अवधि में जिनी गुणांक (जनसंख्या के विभिन्न व्यय वर्गों के बीच असमानता को मापते हुए) का उपयोग करते हुए 2004-05 तथा 2011-12 में क्रमश: 0.27 तथा 0.28 अर्थात लगभग समान रहा। शहरी क्षेत्रों में, जिनी गुणांक 2004-05 के 0.35 से मामूली सा बढ़कर वृद्धि के साथ 2011-12 में 0.37 हो गया। इससे यह पता चलता है कि भारत में असमानता की स्थिति में कोई विशेष गिरावट नहीं हुई है।

(ख) और (ग): सरकार का प्रमुख नीतिगत उद्देश्य आबादी के सभी वर्गों का विकास करना है। सरकार रोजगार के बेहतर अवसर पैदा करने, सामाजिक अवसंरचना को मजबूत बनाने, पानी, बिजली, सड़कें, सफाई और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए अनेक कार्यक्रम/योजनाएं चला रही है। सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) और दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) इत्यादि जैसे कार्यक्रम देश के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना है ताकि मानव आबादी के लाभ प्राप्त किए जा सकें। प्रधानमंत्री जनधन योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बैंक खातों तक पहुंच सुनिश्चित करके वित्तीय समावेशन प्राप्त करने का प्रयास है।

अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का उद्देश्य अत्यधिक गरीब वर्गों को स्थायी आस्तियां और वित्तपोषण सुविधाएं मुहैया कराना है ताकि उनकी आय और उपभोग स्तरों में सुधार हो सके। ऐसे कार्यक्रमों में स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंडअप इंडिया योजना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा तंत्र के दायरे को बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई), अक्तूबर, 2018 से आरंभ की गई जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। यह योजना अस्पताल में भर्ती के दौरान द्वितीयक और उच्चस्तरीय देखभाल उपलब्ध कराने के लिए है। आशा है कि इन हस्तक्षेप कार्रवाइयों से चिकित्सीय आपात स्थिति के कारण गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवारों (एपीएल) को गरीबी में जाने से बचाया जा सकेगा और ऐसी बीमारियों के बोझ से गरीब परिवारों की रक्षा की जा सकेगी।

**\*\*\*\*\***